

डिजीटल इण्डिया: आधुनिक संचार क्रान्ति

¹डॉ० आनन्द गोस्वामी

¹एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष-इतिहास, राजकीय स्ना० महाविद्यालय, चरखारी (महोबा) उ०प्र०

Received: 15 June 2018, Accepted: 15 July 2018, Published on line: 15 Sep 2018

Abstract

डिजीटल इण्डिया, अंकीय भारत के रूप में एक सकारात्मक एवं प्रगतिशील पहल है। इसके अन्तर्गत भारत के लोगों को एक-दूसरे के समीप लाने की भारत सरकार की सार्थक पहल है। सुशासन और अधिक रोजगार हेतु भारत को एक डिजिटल विस्तार देना इसका लक्ष्य है। सभी गाँवों को इन्टरनेट से जोड़ने हेतु फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाया जा रहा है। फलस्वरूप हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिल रही है। डिजीटल इण्डिया के तहत शुरू किये गये वाई-फाई चौपाल योजना से गाँवों की बेटियाँ भी रोजगार पा रही हैं। न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी निःसंदेह लाभान्वित हो रहे हैं।

Keywords:- डिजीटल इण्डिया, डेटा, इण्टरनेट, पेमेन्ट गेट वे, कनेक्टिविटी, स्मार्ट फोन, वाई-फाई, नेट बैंकिंग।

Introduction

डिजीटल इण्डिया अर्थात् अंकीय भारत के रूप में एक सार्थक पहल 1 जुलाई 2015 को दिल्ली के इंदिरा गाँधी इन्डोर स्टेडियम में देश के प्रमुख उद्योगपतियों की उपस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी। इसके अन्तर्गत देश के 600 जिलों तक सूचना तकनीक की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है/क्रियान्वित है।

डिजीटल इण्डिया वस्तुतः सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक सार्थक पहल है। इसके अन्तर्गत किसी भी जरूरी सूचना तक पहुँच के लिये तेज गति के इन्टरनेट नेटवर्क के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से जुड़ने, कागजी कार्यवाही, समय तथा श्रम को घटाने एवं भारतीय नागरिकों को इलेक्ट्रानिक सरकार की सेवा उपलब्ध कराना है। इस हेतु लगभग एक लाख करोड़ के डिजीटल लॉकर, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, ई-हस्ताक्षर आदि स्कीमें क्रियान्वित की जा चुकी हैं। 2019 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का

लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के द्वारा न केवल व्यापक स्तर पर मानव श्रम और उपभोक्ता दोनों का लाभ पहुँचेगा वरन् डिजीटल इण्डिया में डेटा का डिजीटलाइजेशन सरलता से होगा जो भविष्य में चीजों को और ज्यादा तेज और दक्ष बनाने में मदद करेगा।

यह कार्यक्रम देश के लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा। दूर संचार तकनीक मंत्रालय द्वारा इसकी योजना व अध्यक्षता में एक आशाजनक अच्छे प्रतिफल को प्राप्त करने के लिये विभिन्न सरकारी विभाग जैसे— आई—टी, शिक्षा, कृषि आदि के द्वारा ये प्रोजेक्ट परस्पर सम्बद्ध है। सुशासन तथा और अधिक नौकरियों के लिये भारत को एक डिजीटल विस्तार देना इसका लक्ष्य है। अब सभी शहरों, नगरों ओर गाँवों में ब्राडबैंड हाईवे की खुली पहुँच माऊस के एक क्लिक पर विश्व—स्तरीय सेवा की उपलब्धता को मुमकिन बनाया जा रहा है।

प्रमुख विजन— सशक्त समाज और अर्थव्यवस्था को डिजीटल रूप देकर उनकी गति बढ़ाने हेतु तीन प्रमुख विजन निर्धारित किये गये हैं।

1. प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इण्डिया की उपयोगिता से परिचित कराना।
2. नागरिकों की माँग पर शासन और सेवाएँ प्रदान करना।
3. हर नागरिक को डिजीटल शाक्ति प्रदान कराना।

प्रमुख योजनायें— डिजीटल इण्डिया की दो योजनायें उल्लेखनीय हैं।

- डिजीटल लिटरेसी।
- भारत नेट।

उपर्युक्त के अंतर्गत निम्न योजनायें चलायी जा रही हैं—

1. **ब्राडबैंड हाईवे की सुविधा—** सभी गाँवों को इन्टरनेट से जोड़ने हेतु फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक ग्राम—पंचायत को 100 एम बी पी एस की स्पीड से कनेक्टिविटी मिल सके।
2. **स्मार्ट फोन—** हर नागरिक के पास एस स्मार्ट—फोन हो जिससे वो इन्टरनेट की सुविधा व मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग कर सके।

पब्लिक इन्टरनेट एक्सेस कार्यक्रम— इसके तहत सर्व प्रथम पोस्ट—आफिसों को मल्टी—सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे जनता तक पहुँच बढ़ सके।

ई—गवर्नेंस— इसके अन्तर्गत इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना में और सुधार लाना है। इसमें सभी तरह के डेटा—बेस जानकारी को इलेक्ट्रानिक्स रूप दिया जा रहा है। आधार

सुविधा, पेमेंट गेटवे, मोबाइल जैसी जानकारी को एकीकृत किया जा रहा है, फलतः ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हो रही है।

ई-क्रान्ति— इसके अन्तर्गत सभी स्कूल-कालेज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा रही है उन्हें फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जायेगी। सभी तरह के कोर्स को ऑनलाइन किया जा रहा है। इन सुविधाओं को ई-एजुकेशन का नाम दिया गया है। साथ ही ई-हेल्थकेयर, ई-कोर्ट, ई-पुलिस, किसानों के लिए मंडी भाव जैसी अनेक सुविधाएँ मिलना शुरू हो गयी है। इस क्रम में डिजिटल प्रशिक्षण के लिये 6 करोड़ लोगों के लिए बजट की व्यवस्था की गयी थी और लगभग डेढ़ लाख गाँवों में इन्टरनेट पहुँचाया जा चुका है।

निष्कर्ष— डिजिटल इण्डिया के ट्वीट के अनुसार 2014 में मोबाइल फोन निर्माण हेतु मात्र दो फैक्ट्री थी, आज 120 से ज्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, इससे लगभग साढ़े चार लाख नागरिकों को रोजगार मिला हुआ है। डिजिटल इण्डिया के अन्तर्गत शुरू किये गये वाई-फाई चौपाल योजना से गाँवों की बेटियाँ नौकरी पा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कई कारणों से कागजी कार्य करने में लम्बी दूरी, समय तथा पैसा बर्बाद करते रहे हैं, निःसंदेह लाभान्वित हो रहे हैं। ई-कॉमर्स कम्पनियाँ आने से डिलीवरी-बॉय सामने आये, फलतः कुछ युवा रोजगार पा सके तथापि अभी बहुत कुछ करना शेष है। एडवोकेट विराग के शब्दों में सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि, नये किस्म की इकॉनामी के अनुरूप कानून भी बनाए और जबाबदेही तय करे। यथा, व्हाट्सऐप को अगर बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है तो उसका मालिक कौन है, भारत में उसका ऑफिस कहाँ है, उसकी जबाबदेही क्या है ? इसी प्रकार विश्लेषक ओसामा मंजर कहते हैं कि, ग्रामीण इलाकों की 92 प्रतिशत और पूरे देश की 72 प्रतिशत महिलाओं के पास अभी भी मोबाइल फोन नहीं है। उनके अनुसार टी आर ए आई के आँकड़ों में एक अरब लोगों के सिम कनेक्शन की बात की जाती है, न कि इन्टरनेट की। तथापि कहा जा सकता है कि **अंकीय भारत** निःसंदेह सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के नजदीक लाने की भारत सरकार की एक सार्थक पहल है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. डिजिटल इण्डिया : अजय कुमार : प्रभात प्रकाशन : 2018 नई दिल्ली ।
2. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका : अंक 10, अगस्त 2017
3. डिजिटल इंडिया और भारत "विराग गुप्ता, अनन्य प्रकाशन दिल्ली ।
4. डिजिटल इंडिया : हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्ली ।
5. अतुल कुमार— डिजिटल इंडिया (एक समृद्ध राष्ट्र के लिए) करन प्रकाशन, लुधियाना ।
6. दशोरा ज्योति : 2017, शोध पत्र, डिजीटल इंडिया परिसीमन और सम्भावनाएँ ।
7. लोने अहमद जहूरु : 2017, शोध पत्र, भारत में ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव ।